संयुक्त राज्य अमेरिका का श्रम विभाग

बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के बारे में 2023 के निष्कर्ष

भारत

2023 में, भारत ने बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को समाप्त करने के प्रयासों में मध्यम प्रगति की। सरकार ने अपने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का विस्तार किया, जो बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण सहित यौन अपराध के मामलों के लिए सुनवाई प्रक्रिया में शीघ्रता लाते हैं। रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस ने रेलवे प्लेटफार्मों से 858 बच्चों को बचाया, जिससे उन्हें मजदूरी शोषण या यौन तस्करी के लिए शोषण किए जाने से बचाया जा सके। कई राज्यों ने 654 वयस्क बंधुआ मजदूरी से बचे लोगों और उनके निकट परिवारों को पुनर्वास और वित्तीय सहायता प्रदान की। इन प्रयासों के बावजूद, सरकार के मौजूदा खतरनाक कार्य निषेधों में वे सभी व्यवसाय शामिल नहीं हैं जिनमें बच्चे असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करते हैं, और बच्चों को अवैध रूप से काम पर रखने के लिए दंड उल्लंघनों को रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। बाल तस्करी सहित, बाल श्रम के सबसे खराब रूपों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन दरें कम बनी हुई हैं तथा बाल श्रम पीड़ितों के साथ पुलिस द्वारा किया जाने वाला दुर्व्यवहार चिंता का विषय बना हुआ है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के बढ़ते प्रवर्तन के माध्यम से, सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज संगठनों के लाइसेंस निरस्त करना जारी रखा, जिनमें से कुछ बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को संबोधित करने के लिए काम करते हैं।

नीचे सुझाए गए सरकारी कार्य उन कमियों को दूर करेंगे जिन्हें यूएसडीओएल ने बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों को समाप्त करने के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन में पहचाना है।

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाही
क़ानूनी ढांचा	असुरक्षित और अस्वस्थ परिस्थितियों में बच्चों द्वारा किए जाने वाले काम, जैसे कताई मिल, परिधान उत्पादन, कालीन निर्माण और घरेलू काम, को सभी क्षेत्रों में सभी बच्चों के लिए निषिद्ध खतरनाक कामों की सूची में शामिल करें।
	बाल तस्करी कानूनों में संशोधन करें ताकि उनमें बाल तस्करी के अपराध के लिए धमकी, बल प्रयोग या दबाव की आवश्यकता न हो।
	भारत के सशस्त्र बलों में स्वैच्छिक भर्ती के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाला एक कानूनी दस्तावेज प्रकाशित करें। ।
	सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों को खतरनाक प्रकार के काम से सुरक्षित रखने के लिए, व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति की संहिता को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।
प्रवर्तन	लगभग 535 मिलियन लोगों के श्रम बल की पर्याप्त ढंग से निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 35,668 श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति करें और श्रम कानून प्रवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय डेटा प्रकाशित करें।

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाही
	सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाल श्रम पर श्रम निरीक्षकों और आपराधिक जांचकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करें, जिसमें नए व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता पर प्रशिक्षण शामिल है।
	बंधुआ मजदूरी के मामलों पर तेजी से कार्रवाई करें और उल्लंघन के लिए सुसंगत दंड लगाएं।
	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना के लिए, समर्पित और पर्याप्त धन, कर्मचारी और बुनियादी ढांचा प्रदान करें।
	सुनिश्चित करें कि 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के तहत सभी मामले अभियोजन के लिए अपनी अनिवार्य 1-वर्ष की समय-सीमा का पालन करें, कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए और इन न्यायालयों के न्यायाधीशों और अभियोजकों को बाल यौन अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए।
	ऐसे सार्वजनिक अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराएं जो बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों को संबोधित करने के प्रयासों में सहायता करते हैं, उनमें भाग लेते हैं या बाधा डालते हैं, जिनमें रिश्वत लेने वाले, कृषि और ईंट भट्टों में बच्चों को बंधुआ मज़दूरी पर रखने वाले और मानव तस्करी के मामलों को दर्ज करने में देरी करने वाले या मानव तस्करी से बचे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी शामिल हैं।।
	निचली जातियों की लड़कियों को वस्तुगत भुगतान या नकद भत्ते के बदले में यौन शोषण के लिए स्थानीय देवताओं को बेचे जाने से बचाने के लिए <62>जोगिनी </62>प्रणाली के अपराधियों पर मुकदमा चलाएँ और उन्हें उत्तरदायी बनाएँ।
सरकारी नीतियां	सुनिश्चित करें कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, और बाल श्रम पर राज्य कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए गतिविधियाँ की जाती हैं और इन योजनाओं को लागू करने के लिए की गई गतिविधियों के परिणाम प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जाते हैं।
	जिन राज्यों और क्षेत्रों के पास वर्तमान में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कार्य योजनाएँ नहीं है, उन्हें ऐसी योजनाओं को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें।
सामाजिक कार्यक्रम	शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करके, लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराकर, तथा उपलब्ध विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर, विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों में, जहाँ अपर्याप्त अवसंरचना विकल्प शिक्षा तक पहुँच को सीमित करते हैं, निम्न जाति के हिंदुओं, आदिवासी समुदायों के सदस्यों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समुदायों सहित सभी बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा दें और बाधाओं को कम करें।
	प्रत्येक राज्य में शोषणकारी बाल श्रम पर डेटा एकत्र करें और उसे जनता के लिए उपलब्ध कराएँ, जिसमें जिला-स्तरीय बंधुआ श्रम सर्वेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष और राष्ट्रीय जनगणना से प्राप्त कच्चे आंकड़े शामिल हैं।
	सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारें बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करें और बंधुआ श्रम पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें, जिसमें बंधुआ श्रम से मुक्त होने वालों के लिए पूर्ण मुआवजा भी शामिल है।
	बचाए गए बाल श्रम पीड़ितों को श्रम बाजार में उनके पुन: प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त सामाजिक सेवाएं प्रदान करें, जिसमें शैक्षिक पुन: प्रवेश कार्यक्रम शामिल हैं।

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाही
	सुनिश्चित करें कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम का उपयोग बाल श्रम-केंद्रित गैर-सरकारी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय निधि प्राप्त करने या देश में काम करने के लिए उनके लाइसेंस को संरक्षित करने से रोकने के लिए नहीं किया जाता है।
	सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय पर और सुसंगत ढंग से मानव तस्करी आश्रयों के लिए धन उपलब्ध कराएं।
	धार्मिक अल्पसंख्यकों और प्रवासी बच्चों सहित भारत में कमजोर आबादी के बीच बाल श्रम, बंधुआ बाल श्रम और बाल तस्करी को संबोधित करने के लिए सामाजिक कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करना।